पीएम जनमन योजना पर सवाल, बैगा जाति वंचित

वर्ष 2024-25 में जिले के तीनों विकासखण्ड एवं नगरीय क्षेत्र में 449 शिविर आयोजित के दावे

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 6 मई। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जिले में वर्ष 2024-25 में देवसर, चितरंगी एवं अन्य विकासखंडों में कुल 449 पॉच चरणों में शिविर आयोजित किए जाने का दावा किया गया था। इन शिविरों का उद्देश्य विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति बैगा समुदाय के लोगों को चिन्हित कर उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाना था। इस पूरे अभियान की जिम्मेदारी आदिम जाति कल्याण विभाग को नोडल एवं शिविर कराने का जिम्मा शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत के अधीन ग्राम पंचायतों के माध्यम से व्यापक स्तर पर शिविर आयोजित किए गए थे।

लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहीं खड़ा हो रहा है कि जब इतनी बड़ी संख्या में शिविर आयोजित किए गए, तो बैगा समुदाय आज भी मूलभूत योजनाओं से वंचित क्यों है? हाल ही में एनसीएल परियोजना निगाही क्षेत्र की बैगा बस्ती में पिछले दिनों बेरहमी मारपीट के मामले में पीड़ित अन्नेलाल बैगा से जब पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री राधा सिंह, सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह और भाजपा जिलाध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधि के साथ-साथ म.प्र . राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल रौतेले भी पहुंचे, तब जमीनी सच्चाई सामने आई।

बैगा समुदाय के लोगों ने खुलकर अपनी समस्याएं बताईं। उन्होंने कहा कि आज भी उन्हें राशन कार्ड, आधार कार्ड, लाड़ली बहना योजना, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन जैसी मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा उज्ज्वला गैस योजना का लाभ भी इन तक नहीं पहुंचा है।

कई परिवार आज भी पारंपरिक ईंधन पर निर्भर हैं। स्थिति और भी चिंताजनक तब दिखी जब लोगों ने बताया कि बस्ती में न तो पक्की सड़क है और न ही पेयजल की समुचित व्यवस्था। पानी के लिए लोगों को भारी संघर्ष करना पड़ रहा है। बूंद-बूंद पानी के लिए मारामारी जैसी स्थिति बनी हुई है।

हालांकि अब एनसीएल के साथ-साथ नगर निगम के अधिकारियों की नींद टूटी है। संभवत: आज-कल तक में पानी सप्लाई चालू कराने के लिए कवायदे की जा रही हैं।

दूरस्थ अंचलों की स्थिति और भी चिंताजनक होने की आशंका

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी अधिकांश परिवारों को नहीं मिला है और कई लोगों को अब तक भूमि का पट्टा तक नहीं मिला है। गौर करने वाली बात यह है कि यह बस्ती जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इतनी नजदीकी बस्ती का यह हाल है, तो दूरदराज के वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले बैगा समुदाय की स्थिति कितनी दयनीय होगी। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि योजनाएं कागजों में तो सफल दिखाई जाती हैं, लेकिन धरातल पर उनका असर नगण्य है। 449 शिविरों के आयोजन के बावजूद यदि पात्र हितग्राही योजनाओं से वंचित हैं, तो यह व्यवस्था की बड़ी विफलता मानी जा रही है।

प्रदेश सरकार के विकास के दावे की पोल बैगा बस्ती से खुल गई

विपक्षी दल कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि म .प्र . में लंबे समय से सरकार द्वारा विकास के बड़े-बड़े दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन बैगा जैसी संरक्षित जनजाति तक योजनाओं का लाभ न पहुंच पाना इन दावों पर सवाल खड़े करता है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा है कि धरातल पर बैगा जनजनातियों का कितना विकास हुआ है, सरकार की पोल बैगा बस्ती से खुल गई है। जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर जब जिम्मेदार अधिकारी जायजा लेने कभी नही गये तो दूर-दराज, जंगलों एवं पहाड़ों के बीच बसे बैगा जनजातियों की दशा कैसी होगी,उनका रहन-सहन, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी सुदृढ़ होगी, यह तो गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। अब जब मामला उजागर हुआ, तो भाजपा के जनप्रतिनिधि एवं सरकार की नुमाइंदे भागदौड़ कर अपनी नाकामियों को छुपाने में लगे हुये हैं।

बैढ़न के आधा दर्जन गैस रिफीलिंग दुकानों में एसडीएम का छापा

आधा दर्जन से अधिक गैस सिलेण्डर जब्त, मचा हड़कंप

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 6 मई। बैढ़न-विंध्यनगर शहर के आधा दर्जन रिफिलिंग गैस दुकानों में एसडीएम सिंगरौली के अगुवाई में छापामार कार्रवाई की गई। जहां आधा दर्जन से अधिक घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त कर कार्रवाई की गई है।

दरअसल जिले में घरेलू गैस की कालाबाजारी की लगातार शिकायते मिल रही हैं, जिसपर आज एसडीएम सिंगरौली एवं नायब तहसीलदार पंजेरह एवं खाद्य की टीम ने संयुक्त रूप से बैढ़न के करीब आधा दर्जन गैस रिफिलिंग दुकानों में दबिश दी गई, जहां दो दुकानदारों के यहां से 8 गैस सिलेण्डर के साथ-साथ नोजल पाइप जप्त कर कार्रवाई की गई है। एसडीएम ने बताया कि यह कार्रवाई घरेलू गैसों के कालाबाजारी मद्देनजर की गई है। 8 की संख्या में गैस सिलेण्डर जप्त किये गये हैं। उन्होंने बताया कि एसके कीचन वेयर एवं नवभारत इन्टरप्राइजेज में कार्रवाई की गई है।

एक नजर में

ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ

सिंगरौली। संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण, म.प्र. के निर्देशानुसार जिले के छात्र-छात्राओं के ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय के सदुपयोग एवं खेल प्रतिभाओं के विकास के लिए जिला सिंगरौली में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय राजमाता चून कुमारी स्टेडियम में आयोजित यह शिविर 5 मई से शुरू होकर 4 जून तक संचालित होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह द्वारा किया गया। इस अवसर पर पार्षद सीमा जायसवाल, लवकुश कुमार तिवारी एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग से राकेश मिश्रा मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे शिविरों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को सही मंच और मार्गदर्शन मिलता है।

उपार्जित गेंहू का दो दिनों में 90 प्रतिशत परिवहन कराएं

सिंगरौली। रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन की उच्च प्राथमिकता की योजनाओं की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि सभी कलेक्टर समर्थन मूल्य पर गेंहॅू उपार्जन पर विशेष ध्यान दें। उपार्जित गेंहॅू का दो दिनों में 90 प्रतिशत उठाव कराकर सुरक्षित भण्डारण कराएं। स्वीकृति पत्रक तत्काल जारी कराकर किसानों को तीन दिवस में भुगतान कराएं। गेंहू के परिवहन में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। पेयजल व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करें। पेयजल से संबंधित आवेदन पत्रों का 24 घंटे में निराकरण कराएं। सभी जिलों को राइजर पाइप तथा सिंगल फेज मोटर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दिए गए हैं।

आरएनआर कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं : गौरव

साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर का निर्देश

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 6 मई। आरएनआर कॉलोनियों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सहित विस्थापितों के लिए निर्धारित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। साथ ही टीएल बैठक में प्रस्तावित औद्योगिक कंपनियों से संबंधित सभी आवेदन पत्रों का कंपनियां उच्च प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करना सुनिश्चित करें।

उक्त आशय के निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित औद्योगिक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ टीएल पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर गौरव बैनल द्वारा दिए गए। कलेक्टर ने विस्थापितों के लिए निर्मित की गई आरएनआर कॉलोनियों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि कॉलोनियों में ओवरहेड टैंक एवं पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करना आप सभी की पहली प्राथमिकता है। इस संबंध में जल जीवन मिशन की पाइपलाइन का भी सहयोग लिया जा सकता है। इसी के साथ ही कॉलोनियों में सर्वसुविधायुक्त चिकित्सालय एवं विस्थापितों के बच्चों के पठन-पाठन के लिए विद्यालय की उचित व्यवस्था की जाए। बैठक में कलेक्टर ने इस आशय के भी निर्देशित किया कि कंपनियां अपने-अपने क्षेत्रों में विस्थापन से संबंधित सभी पैरामीटर्स का शत-प्रतिशत पालन करें तथा विस्थापितों को पात्रतानुसार लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान सहायक कलेक्टर सौम्या मिश्रा सहित एनसीएल ब्लॉक बी, एपीएमडीसी तथा रिलायंस सासन पावर के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

सिंगरौली को बड़ी सौगात, जिला न्यायालय भवन के लिए बढ़ी बजट की राशि

विधायक रामनिवास शाह के प्रयासों से 70 .22 करोड़ की मंजूरी, सिंगरौली के विकास में नया अध्याय

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 6 मई। जिले के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि सामने आई है। सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह के निरंतर प्रयासों के चलते निर्माणाधीन जिला न्यायालय भवन के लिए म.प्र. शासन ने पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। पहले जहां इस परियोजना के लिए 24.27 करोड़ की राशि स्वीकृत थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 70.22 करोड़ कर दिया गया है।

इस प्रकार 45.95 करोड़ की अतिरिक्त राशि मंजूर होने से न्यायालय भवन के निर्माण को नई गति मिलने की उम्मीद है। यह उपलब्धि विधायक के सक्रिय और प्रभावी प्रयासों का परिणाम मानी जा रही है। इससे न केवल अधिवक्ताओं को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा, बल्कि आम नागरिकों को भी न्यायिक सेवाओं का लाभ अधिक सुगमता से प्राप्त होगा। इस निर्णय के बाद अधिवक्ताओं और जिलेवासियों में हर्ष का माहौल है। सभी ने इसे जिले के विकास और न्यायिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

विधायक ने सीएम, डिप्टी सीएम व प्रभारी मंत्री के प्रति जताया आभार

मार्च माह में आयोजित बजट सत्र के दौरान विधायक के साथ जिला अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और प्रभारी मंत्री से मुलाकात कर न्यायालय भवन के लिए अतिरिक्त बजट की मांग की थी। उसी मांग का यह सकारात्मक परिणाम सामने आया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री डॉ . मोहन यादव, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल एवं प्रभारी मंत्री संपतिया उइके के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। साथ ही विधायक रामनिवास शाह की पहल और समर्पण की सराहना की जा रही है, जिनके प्रयासों से यह बड़ी स्वीकृति संभव हो सकी। नई स्वीकृति मिलने से निर्माणाधीन जिला न्यायालय भवन अब आधुनिक सुविधाओं से युक्त और अधिक सुदृढ़ रूप में तैयार किया जा सकेगा।

बाइपास मैनेजमेंट सिस्टम स्वीकृति का हुआ शुभारंभ

विंध्याचल की स्वदेशी डिजिटल पहल, स्वीकृति एनटीपीसी उत्तरी क्षेत्र में लागू

नवभारत न्यूज

विंध्यनगर 6 मई। एनटीपीसी के उत्तरी क्षेत्र ने डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए ऑनलाइन प्रोटेक्शन बायपास मैनेजमेंट सिस्टम स्वीकृति का शुभारंभ किया।

यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विंध्याचल टीम द्वारा ऑपरेशन और आईटी विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है। इस प्रणाली का औपचारिक उद्घाटन दिवाकर कौशिक, क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक एनएसपीसीएल द्वारा एमएस टीम्स के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर बीएन झा, कार्यकारी निदेशक ओएस, उत्तरी क्षेत्र के सभी परियोजना प्रमुख, महाप्रबंधक तथा टीम विंध्याचल के सदस्य मौजूद रहे। एनटीपीसी में सफलतापूर्वक लागू होने के बाद, इस नवाचार को अब एनटीपीसी के अन्य स्टेशनों में भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत उत्तरी क्षेत्र से की गई है। इस प्रणाली के विकास में सीसी-ओएस, सीसी-डीआई और सीसी-आईटी समूहों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रोटेक्शन बायपास मैनेजमेंट सिस्टम-स्वीकृति का उद्देश्य प्रोटेक्शन बायपास प्रबंधन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाना, संचालन दक्षता में सुधार करना और सुरक्षा मानकों को और मजबूत बनाना है। यह पहल एनटीपीसी की नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता और स्वदेशी डिजिटल समाधानों को अपनाकर बेहतर संचालन एवं सुरक्षित पावर प्लांट प्रबंधन सुनिश्चित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

कामर्शियल गैस मूल्य वृद्धि के खिलाफ आप का प्रदर्शन

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 6 मई। प्रदेश प्रभारी पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के निर्देशन में आम आदमी पार्टी द्वारा संपूर्ण म.प्र. में बढ़े हुए गैस के दाम के विरोध में जिला मुख्यालय में रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय पहुंच कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष शहर लाल बाबू कुशवाहा, प्रदेश सचिव अभिमन्यु देव चंदेल, युवा अध्यक्ष अक्षय शाह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे ।

प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में मण्डलों की बैठक अनिवार्य : सुन्दर

भारतीय जनता पार्टी मंडल बैढ़न की कामकाजी बैठक का हुआ आयोजन

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 6 मई। भाजपा जिला मुख्यालय मंडल बैढ़न की विशेष कामकाजी बैठक जिला कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह मौजूद रहे।

विशिष्ट अतिथि के रूप में मंडल प्रभारी दिग्विजय सिंह ध्रुव, जिला उपाध्यक्ष पूनम गुप्ता, प्रदीप शाह, विजया सिंह, महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री सीमा जायसवाल, जिलामंत्री संदीप झा, पूर्व जिला महामंत्री संतोष वर्मा, राजकुमार दुबे, वरिष्ठ नेत्री मधू झा, जिला मीडिया प्रभारी नीरज सिंह परिहार मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए मंडल प्रभारी दिग्विजय सिंह ने कहा कि संगठन द्वारा तय मापदंडों पर अब नियमित रूप से मंडल की बैठक होगी तथा वो प्रत्येक शक्ति केंद्रों एवं बूथों पर स्वयं पहुंच कर बैठके लेंगे तथा हर सांगठनिक गतिविधी की पूर्णता उनका लक्ष्य होगा। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमारे केंद्रीय संगठन द्वारा सांगठनिक कार्यों की नई रूप रेखा तय कर दी गई है, जिसके अनुसार प्रत्येक मास के 1 तारीख से 7 तारीख के बीच मंडलों की कामकाजी बैठक करना अनिवार्य है तथा बैठकों मे अपेक्षित कार्यकर्ताओं की श्रेणी भी निर्धारित है। बैठक में मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष नीरज पांडेय, मकरध्वज सिंह, मंडल प्रभारी शारदा शर्मा एवं समस्त भाजपा पार्षद तथा शक्ति केंद्र संयोजक मौजूद रहे।

एनसीएल जयंत में हेलमेट जागरुकता अभियान आयोजित

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 6 मई। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर चलाए जा रहे हेलमेट जागरूकता अभियान के तहत थाना यातायात सिंगरौली द्वारा एनसीएल जयंत क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।

यातायात पुलिस टीम ने एनसीएल कर्मचारियों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट के अनिवार्य उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि हेलमेट दुर्घटना के समय सिर को गंभीर चोटों से बचाने का सबसे प्रभावी साधन है। कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों से अपील की गई कि वे न केवल स्वयं हेलमेट का उपयोग करें, बल्कि अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। साथ ही हेलमेट की स्ट्रिप ठीक से बांधने और सभी यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी गई। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। 26 अप्रैल से अब तक 730 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है, जिनमें से 400 चालान हेलमेट न पहनने पर किए गए हैं।

नाश्ता वितरण में अनियमितता पर नोटिस जारी

आंगनबाड़ी केंद्रों का परियोजना अधिकारी ने किया निरीक्षण

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 6 मई। परियोजना अधिकारी शहरी परियोजना द्वारा आज पंजरेह झिंगुरदह बस्ती क्षेत्र के तीन आंगनबाड़ी केंद्रों, कांटा बैरियर झिंगुरदह, चन्द्रपुर एवं खैरवाही बस्ती झिंगुरदह का सघन निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान तीनों केंद्र संचालित पाए गए, जहाँ बच्चों की लंबाई एवं वजन का भौतिक सत्यापन सीधे पोषण ट्रैकर एप के माध्यम से किया गया। समीक्षा के दौरान केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं का पंजीयन कम पाए जाने पर परियोजना अधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। वहीं स्व-सहायता समूहों द्वारा भोजन तो मीनू के अनुसार वितरित किया जा रहा था, किंतु नाश्ता वितरण में निर्धारित मीनू का पालन नहीं करने पर संबंधितों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। टीकाकरण की स्थिति संतोषजनक रही।

नल-जल योजना की खुली पोल, सरई में अधूरा काम बना जानलेवा

सड़के खोदकर छोड़ीं, गड्ढों से बढ़ा हादसों का खतरा, ट्रायल में ही फेल सप्लाई, जगह-जगह पाइपलाइन लीकेज, प्रशासन और ठेकेदारों पर लापरवाही के गंभीर आरोप

नवभारत न्यूज

सरई 6 मई। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल, हर घर जल योजना सरई क्षेत्र में जमीनी स्तर पर पूरी तरह विफल नजर आ रही है।

वर्ष 2024-25 की तय समय-सीमा बीत जाने के बाद भी योजना अधूरी पड़ी है और जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। विकास के नाम पर क्षेत्र की सड़कों को खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। धनौजा मंदिर के सामने की स्थिति सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है। यहां पाइपलाइन बिछाने के लिए महीनों पहले गड्ढे खोदे गए थे, लेकिन अब तक उनकी मरम्मत नहीं की गई। खुले गड्ढे दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं और रोजाना लोग जोखिम उठाकर आवागमन करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि योजना के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई है। स्थिति तब और चिंताजनक हो गई जब विभाग द्वारा पानी सप्लाई का ट्रायल किया गया। ट्रायल के दौरान ही कई स्थानों पर पाइपलाइन से पानी रिसने लगा, जिससे साफ हो गया कि निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही बरती गई है। लीकेज के कारण पानी की बर्बादी के साथ-साथ सड़कों की हालत और खराब हो रही है। कई जगह गड्ढे और चौड़े हो गए हैं। जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाना था, लेकिन सरई क्षेत्र के कई मोहल्लों में आज भी लोग इस सुविधा से वंचित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदार विभाग और ठेकेदार पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं और शिकायतों के बावजूद कोई सुधार नहीं किया जा रहा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत कराई जाए, पाइपलाइन की खामियों को दूर किया जाए और दोषी ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई हो। चेतावनी दी गई है कि यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो जनआंदोलन किया जाएगा।